दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 ‖ Postal Registration No-055/Raigarh DN CG ‖ रायगढ़, बुधवार 18 अगस्त 2021 ‖ पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए ‖ वर्ष-03, अंक- 318

महत्वपूर्ण एवं खास

32 नई लो-फ्लोर एसी बसों को मिली हरी झंडी, बेड़े में अब 6,793 बसें

नईदिल्ली (आरएनएस)। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने सोमवार को 32 लो-फ्लोर एसी बसों के बेड़े को हरी झंडी दिखाई। नई शामिल बसें दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी-मॉडल ट्रांजिट सिस्टम की क्लस्टर योजना के तहत होंगी। 32 बसों के जुड़ने से दिल्ली की बसों का बेड़ा 6,793 का हो गया, जिनमें से 3,760 दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) के तहत और 3,033 क्लस्टर योजना के तहत हैं। इस समय क्लस्टर बसें 306 शहर मार्गो पर संचालित की जाती हैं। अतिरिक्त 32 बसें चार अतिरिक्त क्लस्टर रूटों - 993, 380, 390 और 244 पर तैनात की जाएंगी। गहलोत ने कहा कि नई बसें अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस हैं, जिनमें पैनिक बटन, जीपीएस और सीसीटीवी कैमरे शामिल हैं, जिनमें आपातकालीन स्थितियों के लिए लाइव-स्ट्रीमिंग सुविधा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने मार्च 2020 से 452 नई बसों को जोड़कर राष्ट्रीय राजधानी में सार्वजनिक बसों के मौजूदा बेड़े को मजबूत किया है। क्लस्टर योजना के तहत फरवरी 2020 में 100 लो फ्लोर एसी बसों की पहली खेप शुरू की गई थी।

वी.ओ.सी. बंदरगाह ने 24 घंटे में 57, 090 टन कोयला उतारकर नया रिकॉर्ड बनाया

नईदिल्ली (आरएनएस)। वी.ओ. चिदम्बरनार बंदरगाह ने 15.08.2021 को पोत 'एम.वी.स्टार लौरा' से बर्थ संख्या 9 पर 24 घंटे में 57,090 टन कोयला उतारकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। इससे पूर्व, 27.10.2020 को पोत 'एम.वी. ओशन ड्रीम' से बर्थ संख्या 9 पर 56,687 टन कोयला उतारने का रिकॉर्ड था। यह भी गर्व की बात है कि एक दिन में प्रबंधित 1,82,867 टन कार्गो इस वर्ष एक दिन में संचालित कार्गो की सर्वाधिक मात्रा है। मार्शल द्वीप समूह ने मैसर्स इंडिया कोक एंड पॉवर प्राइवेट लिमिटेड के लिए 77,675 टन कोयले की खेप के साथ इंडोनेशिया के मोराबेराऊ बंदरगाह से 14.20 मीटर फ्लोटिंग ड्राफ्ट के साथ पैनामैक्स श्रेणी के पोत 'एम.वी.स्टार लौरा' को फ्लैग किया। तूतीकोरिन की मैसर्स इम्?कोला क्रैन कम्पनी द्वारा संचालित 3-हार्बर मोबाइल क्रैनों ने 24 घंटे के भीतर 57,090 कोयला उतारा। पोत के लिए शिपिंग एजेंट मैसर्स जेएंडपी शिपिंग एजेंसीज तूतीकोरिन तथा स्ट्रीवडोर एजेंट मैसर्स चेट्टीनाड लॉजिस्टिक्स थे। वी.ओ.सी. पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष टी.के. रामचन्द्रन ने हितधारकों द्वारा प्रदर्शित तालमेल की सराहना की, जिन्होंने इस रिकॉर्ड को बनाने में योगदान दिया है और कहा कि बंदरगाह ट्रैफिक की और अधिक मात्रा आकर्षित करने के लिए निष्पादन और उत्पादकता में सुधार लाने का लगातार प्रयास कर रहा है।

हेलीकॉप्टर के साथ चार कारों में कैश लेकर भागे थे राष्ट्रपति अशरफ गनी

काबुल। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी कुछ दिनों पहले तक जनता से यह कहते रहे थे कि वो देश छोड़कर नहीं जाएंगे, लेकिन रविवार को जब वो देश छोड़कर गए तब वो अपने साथ कैश से भरी चार कार और हेलीकॉप्टर लेकर गए हैं। जानकारी के अनुसार समय के अभाव में बड़ी मात्रा में वो बाकी धन अपने साथ नहीं ले जा सके। तालिबान के डर से अफगानिस्तान छोड़कर रविवार को भागे राष्ट्रपति अशरफ गनी के बारे में यह दावा एक रिपोर्ट में किया गया। रूसी न्यूज एजेंसी आरआईए और कुछ प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अशरफ गनी को कुछ पैसा छोड़कर ही जाना पड़ा क्योंकि वह उसे रख नहीं पा रहे थे। काबुल में रूसी दूतावास के प्रवक्ता निकिता इंशचेन्को ने कहा कि चार कारें कैश से भरी हुई थीं। उसके बाद उन्होंने कुछ रकम हेलीकॉप्टर में रखी। इसके बाद भी वह पूरा पैसा नहीं रख पाए और कुछ पैसे यूं ही छोड़कर निकल गए। फिलहाल अशरफ गनी कहां हैं, यह किसी को भी मालूम नहीं है। हालांकि रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि वह ओमान पहुंच गए हैं और उन्हें ताजिकिस्तान और कजाकिस्तान ने अपने देश में आने की अनुमति नहीं दी। कहा जा रहा है कि वह ओमान होते हुए अमेरिका निकलने की तैयारी में हैं।

अफगान में फंसे भारतीयों निकालने में लगी भारत सरकार, विदेश मंत्री ने अमेरिका से की चर्चा

नई दिल्ली (आरएनएस)। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से ही हाहाकार मच गया है। हजारों लोग देश छोड़कर जाने के लिए काबुल एयरपोर्ट पर भीड़ जमाए हुए हैं। ऐसे में ही कुछ भारतीय भी वहां फंसे हुए है जो मदद के लिए भारत सरकार की तरफ देख रेह हैं और सरकार उनकी हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। भारत अफगानिस्तान से भारतीय राजदूत समेत 120 भारतीय को सुरक्षित भारत लेकर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री से भारतीयों को निकालने में अमेरिकी सहायता लेने के लिए आज न्यूयॉर्क में चर्चा की है।

भारत काबुल से अपने नागरिकों के दूसरे जत्थे को निकालने के लिए पूरी तरह तैयार है, अमेरिकी विदेश मंत्री ने जयशंकर को नागरिक उड़ानों के माध्यम से भविष्य में निकासी में पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका

के विदेश सचिव एंटनी ब्लिंकेन के बीच अफगानिस्तान के मुद्दे पर चर्चा की. इसके बाद उन्होंने ट्वीट कर कहा कि एंटनी ब्लिंकेन के साथ अफगानिस्तान की हालिया घटनाओं पर चर्चा की. काबुल में हवाई अड्डे के संचालन को बहाल करने की तात्कालिकता को रेखांकित किया. मैं इस संबंध में चल रहे अमेरिकी प्रयासों की गहराई से सराहना करता हूं। उन्होंने अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ अफगानिस्तान में ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा भी की और कहा, हमने काबुल में हवाईअड्डा संचालन बहाल करने की अत्यधिक आवश्यकता पर बल दिया। हम इस संबंध में अमेरिकी प्रयासों की बहुत सराहना करते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने बताया कि दोनों शीर्ष राजनयिकों ने अफगानिस्तान संबंधी हालात पर चर्चा की।

जयशंकर आज यूएनएससी के सदस्यों से अफगानिस्तान मुद्दे पर व्यापक सहमति बनाने के साथ-साथ उसी ज्वलंत मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात करेंगे। भारतीय विदेश मंत्री दो दिनों के लिए आतंकवाद और शांति स्थापना पर यूएनएससी सत्र की अध्यक्षता करेंगे। जयशंकर ने ट्वीट किया, अफगानिस्तान में घटनाक्रमों पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आज महत्वपूर्ण चर्चा। अंतरराष्ट्रीय समुदाय की चिंताओं को जताया। संयुक्त राष्ट्र में मेरे कार्यक्रमों के दौरान इन पर चर्चा की उम्मीद है। सिलसिलेवार किए गए ट्वीट्स में जयशंकर ने कहा कि वह काबुल में स्थिति पर लगातार नजर रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत लौटने वाले लोगों की बेचैनी समझता हूं। हवाईअड्डे का संचालन मुख्य चुनौती है। इस संबंध में साझेदारों के साथ चर्चा की गयी है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत काबुल में सिख और हिंदू समुदाय के नेताओं के लगातार संपर्क में है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी एस तिरुमूर्ति ने ट्वीट कर बताया कि जयशंकर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस के साथ संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय पर उसके शांतिरक्षा स्मारक पर एक कार्यक्रम में भाग लेंगे।

देश में पिछले 24 घंटों में 88 लाख 13 हजार से अधिक टीके लगाए गये

» स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.51 प्रतिशत हुई

» भारत ने एक दिन में सबसे ज्यादा टीके लगाने का बनाया रिकार्ड

नईदिल्ली (आरएनएस)। देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत पिछले 24 घंटों में भारत ने टीके की 88.13 लाख से अधिक खुराकें लगाई। हमारे अभियान के शुरू होने के बाद से एक दिन में ये सबसे ज्यादा टीके लगाये गये हैं। इसके साथ ही कोविड-19 टीकाकरण कवरेज कल 55 करोड़ के पड़ाव पर पहुंच गया। आज सात बजे सुबह तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार 62,12,108 सत्रों के जरिये टीके की कुल 55,47,30,609 खुराकें लगाई गईं।

सबके लिये कोविड-19 टीकाकरण का नया अध्याय 21 जून को शुरू हुआ था। केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा बढ़ाने और इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिये कटिबद्ध है। भारत में रिकवरी दर 97.51 प्रतिशत है। यह मार्च 2020 के बाद से सर्वाधिक है।

महामारी की शुरुआत से जितने लोग संक्रमित हुये हैं, उनमें से 3,14,48,754 मरीज कोविड-19 से पहले ही उबर चुके हैं, और पिछले 24 घंटों में 36,830 मरीज स्वस्थ हुये हैं। 154 दिनों में भारत में दैनिक नये मामलों में सबसे कम (25,166) मामले दर्ज किये गये।

लगातार 51 दिन से 50 हजार से कम दैनिक मामले आ रहे हैं। यह केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मिले-जुले और सतत प्रयासों का नतीजा है।

भारत में सक्रिय मामलों की संख्या 3,69,846 दर्ज की गई है, जो 146 दिनों में सबसे कम है। सक्रिय मामले अब देश के कुल पॉजिटिव मामलों का 1.15 प्रतिशत रह गये हैं।

संविधान और मौलिक अधिकारों के हनन पर चुप रहना पाप: सोनिया

नई दिल्ली (आरएनएस)। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने देश की आजादी का 75वां वर्ष आरंभ होने के मौके पर सोमवार को लोगों से इसको लेकर आत्म अवलोकन करने का आह्वान किया कि आजादी के क्या मायने हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि जब मौलिक अधिकारों और संविधान को कुचला जा रहा हो, तब चुप रहना पाप है। उन्होंने कहा कि देश के लोकतंत्र को फिर से सही स्थिति में लाने की जरूरत है।

कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने सोनिया गांधी के लेख का हवाला देते हुए कहा, जब हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा गारंटी के तौर पर दिए गए लोगों के मौलिक अधिकारों को कुचला जा रहा है, तब चुप रहना पाप है। उन्होंने कहा कि इस लेख में कांग्रेस अध्यक्ष ने इस बारे में बात की है कि लोगों के लिए आजादी के 75 साल के क्या मायने हैं। इस लेख में सोनिया गांधी ने कहा कि जब सरकार संसद पर 'हमले करती है' और परंपराओं को 'कुचलती है', लोकतंत्र को 'गुलाम बना देती है' और संविधान का 'हनन करने' का प्रयास करती है तो देश के लोगों को इस बारे में विचार करने की जरूरत है कि आजादी के क्या मायने हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग गांधी का चश्मा उधार ले सकते हैं मगर उनकी दृष्टि गोडसे की ही रहेगी। सोनिया ने कहा कि कोविड-19 और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों को लेकर भारत की प्रतिक्रिया दुनिया के लिए निर्णायक होगी।

सबरीमाला मंदिर में दर्शन के लिए अपने पिता के साथ जा सकेंगी 10 साल से कम उम्र की लड़कियां

» केरल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

तिरूवनंतपुरम (आरएनएस)। सबरीमाला मंदिर मामले में केरल हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है. अब 10 साल से कम उम्र की लड़कियों को भी अपने पिता के साथ सबरीमाला मंदिर में प्रवेश करने की इजाजत दे दी गई है. केरल हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अब10 साल से कम उम्र की लड़कियां अपने पिता के साथ सबरीमाला मंदिर में दर्शन

के लिए जा सकती हैं.

दरअसल इस मामले में 9 साल की एक बच्ची ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी जिसमें उसने 23 अगस्त को अपने पिता के साथ सबरीमाला मंदिर जाने की अपील की थी. बच्ची का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने कहा कि वह 10 साल की होने से पहले सबरीमाला जाना चाहती है क्योंकि तब वह चार दशकों से अधिक समय तक मंदिर नहीं जा सकेगी.

कोर्ट ने कहा, हमारा विचार है कि याचिकाकर्ता को 23 अगस्त को दर्शन के लिए अपने पिता के साथ सबरीमाला जाने की अनुमति देने के लिए एक अंतरिम आदेश जारी किया जा सकता है.

इसी तरह का एक और फैसला कोर्ट ने इस साल अप्रैल में भी दिया था में जिसमें कहा गया है कि बच्चे सभी गतिविधियों में टीकाकरण वाले व्यक्तियों के साथ जा सकते हैं.

यह मंदिर लगभग 800 साल पुराना है. इस मंदिर को लेकर मान्यता है कि भगवान अयप्पा ब्रह्मचारी हैं. इसी वजह से युवा महिलाओं का प्रवेश वर्जित है. 2006 में मंदिर के मुख्य ज्योतिषि परप्पनगडी उन्नीकृष्णन ने कहा था कि मंदिर में स्थापित अयप्पा अपनी ताकत खो रहे हैं.

पेगासस जासूसी: सुप्रीम कोर्ट ने दी इन बातों को गुप्त रखने की छूट

नई दिल्ली (आरएनएस)। इजराइली सॉफ्टवेयर पेगासस से कथित जासूसी की जांच को लेकर दायर याचिकाओं पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दिया और कहा कि इस पर सार्वजनिक बहस नहीं हो सकती है। सर्वोच्च अदालत ने सरकार को नोटिस जारी करते हुए 10 दिन बाद दोबारा इस विचार करने की बात कही है। हालांकि कोर्ट ने यह भी साफ किया कि सरकार को ऐसा कुछ खुलासा करने की जरूरत नहीं है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता हो।

चीफ जस्टिस एन वी रमण, जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की तीन सदस्यीय बेंच ने यह टिप्पणी सरकार के यह कहने के बाद की कि हलफनामे में सूचना की जानकारी देने से

राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा जुड़ा है। पीठ ने कहा कि उसने सोचा था कि सरकार एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करेगी लेकिन इस मामले में सिर्फ सीमित हलफनामा दाखिल किया गया। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह 10 दिन बाद इस मामले को सुनेगी और देखेगी कि इसमें क्या प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए।

केंद्र ने कहा- हम अपने रुख पर कायम - केंद्र का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि सरकार ने सोमवार को दाखिल हलफनामे में अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया था। मेहता ने पीठ को बताया, हमारी प्रतिक्रिया वही है जो हमने सम्मानपूर्वक अपने पिछले हलफनामे में दी थी। कृपया इस मामले को हमारे नजरिए से देखें क्योंकि हमारा हलफनामा पर्याप्त है। भारत सरकार देश की सर्वोच्च अदालत के सामने है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने हलफनामे में कहा था कि वह वह सभी पहलुओं के निरीक्षण के लिए विशेषज्ञों की एक समिति का गठन करेगी और यह समिति शीर्ष अदालत के सामने अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा, छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है और इस मामले से राष्ट्रीय सुरक्षा का पहलू जुड़ा है। मेहता ने कहा कि यह मामला सार्वजनिक बहस का मुद्दा नहीं हो सकता और विशेषज्ञों की समिति शीर्ष अदालत को रिपोर्ट देगी।

राष्ट्रीय सुरक्षा पर कोई शब्द नहीं चाहते: कोर्ट- मेहता ने कहा कि यह एक संवेदनशील मामला है जिसे संवेदनशीलता से निपटा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार इस्तेमाल किए जा रहे सुरक्षा तंत्र के बारे में जानकारी सार्वजनिक तौर पर नहीं दे सकती है। पीठ ने मेहता से कहा कि वह ऐसी कोई चीज नहीं चाहती जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता हो। अगर सक्षम प्राधिकार हमारे सामने हलफनामा दायर करे तो इसमें क्या परेशानी है। हम राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में कोई शब्द नहीं चाहते। मेहता ने कहा कि वह यह नहीं कह रहे कि सरकार किसी को कुछ नहीं बताएगी और दलील यह है कि वह इसे सार्वजनिक तौर पर नहीं कहना चाहती।

इशरत जहां की जमानत अर्जी पर सुनवाई 20 अगस्त तक टली

नईदिल्ली (आरएनएस)। कोर्ट ने दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में आरोपी कांग्रेस की पूर्व पार्षद इशरत जहां की जमानत अर्जी पर सुनवाई 20 अगस्त तक के लिए टाल दी है. सरकारी वकील ने जमानत याचिका पर बहस के लिए और समय मांगते हुए कहा कि वह हवा में बात नहीं कर सकते, जिसके बाद अदालत ने सुनवाई को स्थगित कर दिया.

इस मामले में इशरत जहां और कई अन्य लोगों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज है और उन पर फरवरी 2020 की हिंसा के साजिशकर्ता होने का आरोप है। इस हिंसा में 53 लोग मारे गए थे.

दिल्ली पुलिस की ओर से विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद सोमवार को जमानत याचिका पर बहस करने वाले थे, लेकिन उन्होंने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत से यह कहते हुए सुनवाई टालने की मांग की कि उन्हें इस मामले में तथ्य तैयार करने के लिए कुछ और समय चाहिए.

इशरत जहां की ओर से पेश हुए वकील प्रदीप तेवतिया ने सुनवाई टालने के अनुरोध पर आपत्ति जताई और एएसजे रावत को अवगत कराया कि मामला पिछले छह महीने से लंबित है.

देश के तमाम खनन क्षेत्रों के आसपास 19 अगस्त को शुरू होगा 'ग्रो ग्रीनिंग' अभियान

» कोयला मंत्रालय का 'वृक्षारोपण अभियान-2021

नईदिल्ली (आरएनएस)। कोयला मंत्रालय की कोयला/लिग्नाइट पीएसयू ने इस वर्ष के दौरान बायो-रिक्लेमेशन / प्लांटेशन के अंतर्गत 2,385 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करने के लिए 'ग्रो ग्रीनिंग' अभियान के तहत एक महत्वकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। 19 अगस्त को आरंभ होने वाले 'ग्रो ग्रीनिंग' अभियान को केन्द्रीय कोयला, खनन तथा संसदीय मामले मंत्री प्रल्हाद जोशी द्वारा कोयला, खनन तथा रेलवे राज्य मंत्री रावसाहेब पाटिल दानवे की उपस्थिति में लांच किए जाने

वाले 'वृक्षारोपण अभियान-2021' से गति मिलेगी। ऐसी उम्मीद है कि 19 अगस्त को इस अभियान के दौरान लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये देशभर के कोयला क्षेत्रों के आस-पास के 300 से अधिक वृक्षारोपण स्थल कनेक्ट किये जाएंगे।

'वृक्षारोपण अभियान-2021' जो कोयला क्षेत्र में आजादी का अमृत महोत्सव समारोह का प्रमुख कार्यक्रम है, से निश्चित रूप से खनन प्रचालनों में पर्यावरण निरंतरता आएगी तथा यह कोयला क्षेत्र को ऑपरेट करने का सामाजिक और पर्यावरण संबंधी लाइसेंस प्राप्त करने में मदद करेगा, जो आने वाले दिनों में बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा, जब नई कंपनियों को शामिल करने के लिए और अधिक खदानों को खोला जाएगा। इसके अतिरिक्त, इस अभियान से समाज और आम लोगों को उनके निकटवर्ती क्षेत्रों में वृक्षारोपण की अधिक से अधिक पहल करने के लिए संवेदनशील बनाने तथा प्रेरित किये जाने की उम्मीद है।

तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था के रूप में भारत एक तरफ ऊर्जा क्षेत्र को डीकार्बोनाइज़ करने की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने तथा दूसरी तरफ देश की बढ़ती ऊर्जा मांग, जोकि इसके सामर्थ्य तथा उल्लेखनीय स्वदेशी उपलब्धता के कारण मुख्य रूप से कोयले पर निर्भर है, को पूरी करने की दोहरी चुनौती का सामना कर रहा है। इस प्रकार हमारे कोयले क्षेत्र को विभिन्न विकासगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश की ऊर्जा मांग की पूर्ति में भविष्य में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है, वहीं इसे पर्यावरण तथा समाज की दिशा में जिम्मेदार भी रहना है। इस पृष्ठभूमि में, भारत का कोयला क्षेत्र निरंतर खनन को बढ़ावा देने के लिए कई नवोन्मेषी पहल करता रहा है।

खनन क्षेत्रों के आस-पास 'ग्रो ग्रीनिंग' अभियान एक प्रमुख पहल रहा है, जो न केवल स्थानीय वातावरण में सुधार ला रहा है, बल्कि जलवायु परिवर्तन के कारणों को कम करने के लिए अतिरिक्त कार्बन सिंक का भी निर्माण कर रहा है। इसके अतिरिक्त, हमारी कोयला कंपनियों का लक्ष्य व्यापक पौधारोपण तथा स्वच्छ कोयला प्रौद्योगियों को अपनाने जैसे विभिन्न पर्यावरण अनुकूल उपायों के जरिये कार्बन न्यूट्रेलिटी अर्जित करना भी है।